परिणामी बजट वर्ष 2026-27

विभाग- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,नगर प्रशासन,छत्तीसगढ़

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2026-27	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
1	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के स्थान प वर्ष 2014-15 से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन लागू किया गया है। जिसमें निम्नांकित घटक शहरी गरीबों के लिए क्रियान्वयन होंगे:- 1. सामाजिक जुड़ाव एवं संस्थागत विकास 2. कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार 3. स्व-रोजगार कार्यक्रम 4. क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण 5. शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता 6. शहरी बेघरों के लिए आश्रय की योजना 7. प्रशासनिक एवं अन्य व्यय 8. सूचना संप्रेषण मद	10000	**1.** स्वयं सहायता समूह का गठन-1500 (प्रति समूह 10-15 सदस्य), स्वयं सहायता समूह हेतु आवर्ती निधि-2000, एरिया लेवल फेडरेशन का गठन-50, एरिया लेवल फेडरेशन हेतु आवर्ती निधि-25, टाऊन लेवल फेडरेशन का गठन-5, वित्तीय समावेशन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम-100 **2.** व्यक्तिगत ऋण प्रकरण-2000, समूह ऋण-30 **3.** स्वयं सहायता समूहों हेतु बैंक लिंकेज अंतर्गत ऋण-2000 **4.** विशेषज्ञों के नियुक्ति राज्य स्तर पर-6 / शहर स्त पर-75, सामुदायिक संगठक-208 **5.** वेंडिंग प्लान का चिन्हांकन एवं निर्माण-08, शहरी प विक्रेताओं हेतु प्रशिक्षण-150 **6.** नवीन आश्रय स्थल निर्माण-5, नवीन आश्रय स्थल हे सामग्री क्रय-27, आश्रय स्थलों के संचालन रख-रखा - 20 **7.** प्रशासकीय व्यय हेतु **8.** उत्कृष्ट कार्यो के विडियो फिल्म निर्माण अन्य प्रचार प्रसार	
2	आदर्श शहर समृद्धि योजन	विभिन्न विकास कार्य-सड़क, ड्रेनेज, जलापूर्ति, परिवहन, पार्क, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामुदायिक सेवाएं, रोजगार, व्यापार, उद्यमिता प्रोत्साहन, ई-गवर्नेंस, स्मार्ट ट्रैफिक, सुरक्षा प्रणालं हरित क्षेत्र, नवीकरणीय ऊर्जा, जल संरक्षण,	2000000		

परिणामी बजट वर्ष 2026-27

विभाग- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,नगर प्रशासन,छत्तीसगढ़

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2026-27	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
		सुझाव, शिकायत निवारण और रिपोर्टिंग प्रणाली एवं अन्य कार्य		रायपुर स्मार्ट सिटी लिमि. अंतर्गत शहर के विकास के लिए राशि रू. 912.03 करोड़ का एससीपी फंड भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है, जिसमें लगभग रू. 802.43 करोड़ के 304 कार्य पूर्ण कर लिए गए है, इसी प्रकार राशि रू. 109.60 करोड़ 8 कार्य प्रगति पर है।	
3	स्वच्छ भारत मिशन	यह केन्द्र प्रवर्तित योजना है । भारत सरकार प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार के स्वच्छ भारत मिशन निम्नलिखित 05 घटक में योजना क्रियान्वयन होंगे:- 1. आईएचएचएल/सीटीपीटी, एस्पीरेशनल टॉयलेट 2. यूज्ड वॉटर मैनेजमेंट 3. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 4. आईईसी एवं बिहेवियर चेंज 5. केपेसिटी बिल्डिंग, स्किल डेव्हलपमेंट एवं नॉलेज मैनेजमेंट	4675000	भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन 2.0 अंतर्गत निम्न घटक निर्धारित किए गये है:- स्वच्छ भारत मिशन 2.0 अंतर्गत भारत सरकार, आवासन और शहरीय कार्य मंत्रालय द्वारा राशि रू. 1243.58 करोड़ के एक्शन प्लान की स्वीकृति प्रदा की गई है। राज्य के 79 नगरीय निकायों में 141 आकांक्षीय शौचालय निर्माण की स्वीकृत प्रदान की ग है एवं 20 नगरीय निकायो में एस.टी.पी. निर्माण (इंटरसेप्सन एवं डायवर्सन डेन सहित) की स्वीकृति प्रदान की गई है।	
4	आवास योजना	प्रधानमंत्री आवास योजना ''सबके लिए आवास योजना'' के अन्तर्गत निम्नलिखित घटक के लि क्रियान्वयन होंगे:- 1. झुग्गी बस्ती पुनर्विकास 2. ऋण से जुड़ी ब्याज 3. सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के साथ भागीद के किफायती आवास का निर्माण 4. लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास	8345000	आवास योजना अंतर्गत 1.32 लाख आवास निर्माण क लक्ष्य है, जिसमें बीपीएल 1 लाख, एएचपी 27 हजा तथा रेन्टल हाऊसिंग 5 हजार शामिल है। अद्यतन 24188 आवास स्वीकृत है, जिनमें 10 आवास पूर्ण 5351 आवासों का निर्माण प्रगतिरत है।	

परिणामी बजट वर्ष 2026-27

विभाग- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,नगर प्रशासन,छत्तीसगढ़

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2026-27	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
5	अमृत मिशन	अमृत मिशन हेतु प्रमुख अवरचना घटक निम्नानुसार है:- 1. जलापूर्ति, जलप्रदाय/आवर्धन योजना 2. सिवरेज सुविधाएं ओर सेटेज प्रबंधन 3. बाढ़ को कम करने के लिए वर्षा जल नाले 4. हरित स्थल तथा बाल उद्यान निर्माण कार्य	5120000	प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में मिशन अमृत 2. योजना, सीवरेज योजना, उद्यान निर्माण एवं वॉटर बॉ रिज्यूविनेशन कार्य का क्रियान्वयन किया जावेगा।	
6	मूलभूत सुविधाओं हेतु अनुदान	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसानुसार नगरीय निकायों को कार्ययोजना अनुसार आदिवासी उपक्षे अनुसूचित जाति उपयोजना एवं सामान्य क्षेत्रों के निकायों को पेयजल, प्रकाश, सार्वजनिक शौचाल साफ-सफाई एवं अन्य आवश्यक मूलभूत सुविघाओं लिए अनुदान	900000	192 नगरीय निकायों के लिए निम्नाकिंत कार्य योजना है:- 1. सीसी रोड निर्माण 2. नाली निर्माण 3. डब्ल्यू बीएम रोड निर्माण 4. प्रकाश व्यवस्था 5. सामुदायिक भवन 6. पुल/पुलिया निर्माण	
7	नगरीय निकायों की अधोसंरचना विकास योजना	नगरीय निकायों को अधोसंरचना विकास की योजनाओं हेतु अनुदान एवं ऋण	7500000	प्रदेश की 192 स्थानीय निकायों में अधोसरचना विक अंतर्गत विभिन्न विकास कार्य अंतर्गत निम्नानुसार का किये जाते है :- 1. सीसी रोड निर्माण 2. नाली निर्माण 3. डब्ल्यू बीएम रोड़ निर्माण 4. प्रकाश व्यवस्था 5. सामुदायिक भवन 6. पुल/पुलिया निर्माण	
8	मुख्यमंत्री मितान योजना	प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के प्रत्येक शासकीय का	500000		

परिणामी बजट वर्ष 2026-27

विभाग- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,नगर प्रशासन,छत्तीसगढ़

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2026-27	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
		सुनियोजित तरीके से संचालित हों और राज्य के नागरिकों को बिना किसी व्यवधान के सभी शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सके।		प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में योजना का क्रियान्वयन किया जावेगा।	
9	स्थानीय निकायों को प्रशिक्षण हेतु अनुदान	राज्य के नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को प्रशिक्षित कराना	1898	जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम किये जायेंगे	
10	मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना	निकायों के बुनियादी ढाँचा विकास कार्यो (मुख्य सड़क निर्माण, सड़क चौड़ीकरण, सर्विस रोड निर्माण, फ्लाईओव्हर निर्माण, उद्यान विकास इत्यादि)	4500000	14 नगरीय निकायों के बुनियादी ढ़ाचा विकास कार्य	